# कारोबार की सुगमता के लिए शुल्क ढांचा बदलेगा

**उम्मीदें**

**बजट-2022-23**

नई दिल्ली | गिरीश चंद्र प्रसाद

सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इस दिशा में चीजों को आसान बनाने के लिए वित्त वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में सीमा शुल्क में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। मामले से अवगत एक सूत्र के मुताबिक केंद्र को अप्रचलित शुल्क छूट को समाप्त करने और कई क्षेत्रों में उच्च इनपुट लागत के बारे में उद्योगों के अनुरोध हासिल हुए हैं।

मामले के जानकार व्यक्ति के मुताबिक स्थानीय मूल्य संवर्धन और लागत-प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने पर वित्त वर्ष 2013 के बजट में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बजट में ऐसी धातुओं सहित बुनियादी कच्चे माल पर शुल्क को कम कर सकता है, जिनमें हाल के महीनों में कीमतों में तेजी बढ़ोतरी देखी है। वहीं रियायतें वापस लेने के लिए ऐसे उत्पादों की सूची तैयार की गई है जहां हाल के वर्षों में घरेलू क्षमता में सुधार हुआ है।

परिधान, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक और विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न इंटरमीडिएट में इस्तेमाल होने वाले फास्टनरों और बकल जैसी वस्तुओं के लिए अतीत में दी गई शुल्क रियायतों में कटौती की जी सकती है।

विशेषज्ञों ने कहा कि बजट को कच्चे माल और मध्यवर्ती से लेकर तैयार उत्पादों तक, मूल्य श्रृंखला में शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है, जबकि उद्योग के प्रतिनिधियों ने आतिथ्य जैसे कोविड-प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली आपूर्ति और उपकरणों के लिए सीमा शुल्क राहत का आह्वान किया है।

## बजट आयात प्रक्रियाओं को आसान बना सकता है

ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा ने कहा कि बजट आयात प्रक्रियाओं को आसान बना सकता है। सपरा ने कहा, उद्योग एक विवाद समाधान योजना की उम्मीद कर रहा है और व्यापार करने में आसानी के लिए जीएसटीएन की तरह आयात प्रक्रियाओं को और अधिक डिजिटल बनाने की जरूरत है। उद्योग लॉबी समूह पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने कहा, विकास को सुधारने के लिए, होटल उद्योग द्वारा खरीद पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना महत्वपूर्ण है। मुल्तानी ने कहा कि एयर कंडीशनिंग उपकरण, बिस्तर और गद्दे और फर्नीचर जैसे आइटम, जो होटल उद्योग द्वारा पूंजीगत व्यय की प्रमुख वस्तुएं हैं, 20-25% सीमा शुल्क के अधीन हैं।

mint